भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियाँ ,समस्याएं और सुधार के लिए सुझाव

डॉ.नीलिमा गुप्ताए (प्रभारी–प्राचार्य)दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रायपुर

मोबाइल नं. 9893900134, e- mail- principal.dcms@dishamail.com

सारांश– अमूर्त शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना, आत्म–आश्वासन, दुस्साहस, सही निर्णय लेने और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति को अपने जीवन को उपयोगी और सार्थक तरीके से जीने के लिए निर्देशित करना है। वर्तमान अस्तित्व में शिक्षा प्रणाली में प्रचलित समस्याओं में से एक शिक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता हैय शिक्षा की गुणवत्ता समृद्धि का प्रतिबिंब होती है। समाज में एक व्यक्ति को समृद्ध होने के लिए, शिक्षा को अनिवार्य माना जाता है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याओं को समझना है, जिन मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, वे हैं, शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुद्दे, भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियाँ और सुधार ,वं सुझाव इत्यादि है।

कीवर्ड :– भारतीय शिक्षा प्रणाली, महत्व, मुद्दे, चुनौतियां, सुझाव, सुधार

1 परिचय

भारत में शिक्षा प्रणाली हर साल लाखों स्नातक पैदा करती है, जिनमें से कई सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में कुशल हैं। मानव संसाधन के संबंध में लागू की गई यह प्रगति देश की आर्थिक उन्नति को पुष्ट करती है, दूसरी ओर शिक्षा प्रणाली के भीतर अनेको समस्याएं पैदा करती है। जबकि भारत में जनसांख्यिकी को आम तौर पर इसे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़त प्रदान करने वाला माना जाता है। 15 वर्ष से कम आयु की 35 प्रतिशत आबादी के साथ, भारत की शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों का सामना करती है। एक के बाद एक सरकारों ने शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के छह फीसदी तक बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन वास्तविक खर्च चार फीसदी के आसपास था। शीर्ष बिजनेस स्कूल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और विश्वविद्यालय कर्मचारियों और कर्मियों की कमी का अनुभव करते हैं । शिक्षा को महत्वपूर्ण विकास उपकरण के रूप में देखा गया है। भारत में शिक्षा की व्यवस्था आवंटित संसाधनों और इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या, जिनमें शिक्षक, छात्र और प्रशासक शामिल हैं, दोनों के संदर्भ में एक महान आंदोलन बन गया है। स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत में शिक्षा का सभी स्तरों पर विस्तार हुआ। नियंत्रण के स्तर और प्रबंधन के पैटर्न के आधार परय भारत में शैक्षिक संस्थानों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः–

1 सरकारी संस्थान, जहां वित्त पोषण और प्रबंधन सरकार की जिम्मेदारी है,

2 सरकारी सहायता प्राप्त या अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं

3 निजी उद्यमों द्वारा प्रबंधित हैं, निजी संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं लेकिन सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं

4 पूरी तरह से निजी संस्थान जो न तो वित्त पोषित हैं और न ही सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं

2 शिक्षा की आवश्यकता और महत्व

शिक्षा एक आंदोलन है जिसे मानव संसाधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विकास, जैसे संज्ञानात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, व्यक्तिगत को बढ़ाया जाता है। शिक्षा की प्रणाली में, उच्च शिक्षा में प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, विज्ञान आदि शामिल हैं। ये क्षेत्र व्यक्तियों के बीच ज्ञान, सूचना, मूल्यों और कौशल प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । यह राष्ट्र के विकास और उत्पादकता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज, समुदाय और राष्ट्र का विकास एक अनिवार्य पहलू माना गया हैय केवल शिक्षा के माध्यम से हम मानव संसाधन समुदाय और राष्ट्र के विकास की दिशा में काम कर सकते हैं, जब हम ज्ञान, जागरूकता और कौशल रखते हैं, तब हम ज्ञान, जागरूकता और कौशल का विकास शिक्षा के माध्यम से लागू कर सकते हैं । इसके अलावा, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा में कई अन्य क्षेत्र हैं जैसे गणित, अंग्रेजी, हिंदी, कला, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, होटल प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन आदि जो योगदान देते हैं व्यक्तियों के बीच योग्यता, क्षमताओं और प्रवीणता को समृद्ध करने में देते हैं, ताकि वे अपने वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। शिक्षण संस्थानों में आमतौर पर लोग अपनी रुचि के आधार पर विषय का चयन करते हैं, इसलिए विषय को कुशल तरीके से समझने और रोजगार के अवसरों में इसका उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति को मेहनती, साधन संपन्न, रचनात्मक और सरल होना चाहिए। यह पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने क्षेत्र को कैसे समझता है और इसके लिए कैसे काम करता है। शिक्षक और प्रशिक्षक शिक्षार्थियों को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन शिक्षार्थियों को स्वयं समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से सही मार्ग का अनुसरण करना होता है। राष्ट्र के विकास और उत्पादकता के लिए, सरकार प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च शिक्षा के लिए कुछ सुविधाओं और सब्सिडी की भी आवश्यकता होती है। उच्च

शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में शामिल लागत अधिक है और वर्तमान अस्तित्व में निजी क्षेत्र शैक्षिक संस्थानों के संचालन में योगदान दे रहा है । शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं, व्यक्ति को उन सभी क्षेत्रों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए जो किसी के जीवन को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, जैसे मानदंड, मूल्य, नैतिकता, सामाजिक कौशल, शैक्षणिक ज्ञान, संस्कृतियां, और उन्हें महत्वपूर्ण सोच कौशल का उपयोग करना सीखना चाहिए। . जब कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, प्रबंधक, प्रशासक आदि बन जाता है, तो यह स्पष्ट है कि वह अपने रहने की स्थिति के साथ–साथ अपने परिवार की स्थिति को बनाए रखने के लिए काम करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वह समुदाय के कल्याण के लिए योगदान दे। . शिक्षा और सीखने को व्यक्तियों के जीवन भर लागू किया, उन्हें आजीवन प्रक्रियाओं के रूप में माना जाना चाहिए है और एक व्यक्ति को हमेशा अपने दैनिक जीवन में नई चीजें सीखने पर ध्यान देना चाहिए।

3 भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुद्दे

भारतीय शिक्षा प्रणाली में उभरते हुए मुद्दों को इस प्रकार बताया गया हैः शिक्षण गुण एक निम्न स्थिति में है – देश के अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में, शिक्षण की गुणवत्ता बहुत अविकसित स्थिति में है। वंचित शिक्षण विधियों का नेतृत्व करने वाले मुख्य कारक हैं, शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक विधियों का अच्छी तरह से विकसित नहीं होना, शिक्षण–सीखने के तरीकों को अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं करना, शिक्षकों और छात्रों के बीच उचित संचार की कमी, आधुनिक और नवीन तकनीकों और वित्तीय समस्याओं की कमी इत्यादि इन समस्याओं के कारण, शिक्षण संस्थानों में होने वाला शिक्षण बेहतर गुणवत्ता का नहीं है और इसे उपयोगी बनाने के लिए उपायों को लागू करने की आवश्यकता है ।

वित्तीय बाधाएं – बहुत से छात्र ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समूहों, हाशिए पर और समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। वे अपनी शिक्षा में रुचि दिखाते हैं, मेहनती होते हैं और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यवसाय प्रशासक, शिक्षक आदि जैसे पेशेवर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन उनके परिवारों की कम आय और आर्थिक तंगी शिक्षा के अधिग्रहण के रास्ते में बाधा बनती है। छात्र आमतौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं और ट्यूशन के अलावा, उन्हें अपने रहने, भोजन, किताबें, ई–संसाधनों और अन्य खर्चों के लिए भुगतान करना पड़ता है जो कि उनके बजट से कहीं अधिक है, इसलिए शिक्षा बजट के अनुकूल होनी चाहिए ताकि छात्र कम बजट में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। ऐसे सरकारी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान हैं जो सस्ते हैं लेकिन बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता के मामले में कमी हैं, अतः छात्र निजी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है। अनेको निजी शिक्षा संस्थान हैं जिनके पास अध्ययन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और उपकरण हैं जो उच्च शुल्क की मांग करते हैं । इस असमानता पर काम किया जाना चाहिए और सरकार को शिक्षा को सभी के लिए सस्ती और सुलभ बनाना चाहिए ।

पारंपरिक शिक्षण के तरीके – शैक्षिक संस्थानों में, शिक्षण के पारंपरिक तरीकों को अपनाया जाता है, और शिक्षक शिक्षण में प्रौद्योगिकी या दृश्य–श्रव्य साधनों का उपयोग नहीं करते हैं, खासकर नर्सरी स्कूलों में। शिक्षा प्रणाली के भीतर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की आवश्यकता है। तकनीकी बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश से ग्रामीण जनता के बीच सीखने की सुविधा में योगदान मिलेगा। प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए, नवीन शिक्षण–अधिगम विधियों को अपनाकर और कुशल तरीके से समस्याओं को हल करने के तरीकों को अपनाकर परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों को और अधिक रचनात्मक बनाने की आवश्यकता है

निजीकरणः उच्च शिक्षा का निजीकरण वास्तव में एक नया लेकिन एक वांछित चलन है और संसाधनपूर्णता, अनुकूलनशीलता और श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है। उदारीकरण और वैश्वीकरण का आर्थिक ट्रैक इसकी मांग करता है। भारत में, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान एक साथ कार्य करते हैं। भारत में उच्च शिक्षा का लगभग 50 प्रतिशत निजी संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, । हालांकि, स्थिति को बहुत मामूली नहीं माना जाता है। निजी प्रदाताओं, लाभ को अधिकतम करने के हित में, अपने संस्थानों में उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता पर बातचीत करके लागत को कम करने के लिए हर प्रेरणा रखते हैं।

अपर्याप्त सुविधाएं और बुनियादी ढांचा

शैक्षिक प्रणालियों के कार्य और प्रगति को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक देश की आर्थिक स्थिति है। भले ही भारतीय वर्तमान में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया में छठे स्थान पर है, फिर भी शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित संसाधनों की बड़ी कमी है एक खराब अर्थव्यवस्था यहां की मुख्य समस्या है और इसका परिणाम देश भर के छात्रों के लिए मूलभूत चीजों की कमी है। इस वजह से, छात्रों को उपयुक्त शिक्षण सामग्री की कमी हो जाती है ५ भारत में कुछ मामलों में शैक्षिक संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं और बुनियादी ढांचा नहीं है। शिक्षा के प्रावधान में, यह महत्वपूर्ण है कि मौसम की स्थिति के अनुसार उचित फर्नीचर, प्रौद्योगिकी, मशीनें, ठंडा करने और गर्म करने के उपकरण, साफ शौचालय आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। इन्हें शिक्षा के प्रावधान में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की भौतिक पर्यावरणीय स्थितियाँ आरामदायक होनी चाहिए। सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अविकसित अवस्था में पाया जाता है। इनके कारण, छात्रों के नामांकन में कमी आएगी, इसलिए, सुविधाओं के प्रावधान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चूंकि सरकार अब डिजिटल शिक्षा पर

ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

रचनात्मकता, मूल सोच, अनुसंधान और नवाचार को पुरस्कृत करें – शिक्षा के सभी स्तरों पर, यह महत्वपूर्ण है कि रचनात्मकता, तार्किक और तर्कसंगत सोच, अनुसंधान और नवीन तकनीकों और विधियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। ये सीखने को आनंददायक बनाने में योगदान देंगे। ऐसे छात्र हैं, जो सीखने या कक्षाओं में भाग लेने में रुचि नहीं लेते हैं, इससे अनुपस्थिति की दर में वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षण–अधिगम विधियों में शिक्षकों और प्रशिक्षकों को कल्पनाशील होना आवश्यक है, ताकि वे छात्रों के लिए पाठ योजनाओं को रोचक बना सकें। छात्रों के लिए अनुसंधान तकनीकों को सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उच्च शिक्षा में अनिवार्य हैं। भारत डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। नवाचार से देश के छात्रों और युवाओं के नवोन्मेषी दिमाग को उभारने में मदद मिलेगी। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तन लाएगा और अधिकारियों और सरकार को केवल पुस्तक–शिक्षा के बजाय समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए युवा दिमाग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर है। पूरे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि सभी को समान और निष्पक्ष ज्ञान और विकास के अवसर मिल सकें। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा – शिक्षण का माध्यम विशेष रूप से अंग्रेजी है और अंग्रेजी संस्करण में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के कारण छात्र मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित नहीं कर रहे हैं। और फिर वे अंग्रेजी में अधिक सामग्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप, मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों और गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा हैं । मूल भारतीय भाषाओं में मानक वितरण उपलब्ध नहीं हैं।

कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं – शिक्षण संस्थानों में थ्योरी और किताबों पर बहुत ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। जब ये छात्र परीक्षा पास कर लेते हैं, तो वे व्यावहारिक अनुभव की कमी के कारण पढ़ी हुई सभी चीजों को भूल जाते हैं। भारत में, माता–पिता और शिक्षक अपने छात्रों से अपेक्षा करते हैं कि वे गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बजाय परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करें। और शिक्षा एक चूहा दौड़ बन जाती है। व्यावहारिक ज्ञान और कौशल आधारित शिक्षा अभी भी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्वानों से बहुत दूर है।

प्रतिभा पलायन की समस्या –जब भी चतुर, सक्षम और योग्य उम्मीदवारों को देश में उचित स्थान नहीं मिलता है। रोजगार की तलाश में उन्हें दूसरे देश जाना पड़ता है। इसलिए हमारे राष्ट्र को अच्छी क्षमता से वंचित रखा गया है। इस अजूबे को 'ब्रेन ड्रेन' कहा जाता है। उसके कारण, हमने बहुत सी प्रतिभाओं को खो दिया, जिनका उपयोग हमारे देश में शिक्षा की बेहतरी के साथ–साथ देश के समग्र विकास के लिए किया जा सकता था।

कास्ट रिजर्वेशन और पेड सीट –भारतीय शिक्षा प्रणाली में आरक्षित जाति और अमीर छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं। शिक्षा प्रणाली को सभी छात्रों को उनकी जाति और पंथ के बावजूद समान अवसर देना चाहिए। भारत में एक अच्छे अमीर परिवार के बच्चे को सिर्फ पर्याप्त धन के कारण अच्छी शिक्षा मिल जाती है जबकि एक गरीब परिवार के बच्चे को शायद ही प्राथमिक शिक्षा मिल पाती है। सरकारी आंकड़े इस बेहतर सच्चाई को उजागर करते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले 7 में से केवल 1 बच्चा ही स्कूल जाता है। उस समस्या को जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई गंभीर काम करना चाहिए।

संसाधनों की बर्बादी –हमारी शिक्षा प्रणाली सामान्य शिक्षा पर निर्भर करती है। आवश्यक और सहायक आयामों में ड्रॉपआउट प्रतिशत अधिक है। 7–14 आयु वर्ग के अधिकांश छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। इसका तात्पर्य वित्तीय और मानव संसाधनों की बर्बादी से है।

सामान्य शिक्षा संरचना –हमारी शिक्षा संरचना प्रकृति में सामान्य शिक्षा की है। विशिष्ट और व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति बहुत अस्वीकार्य है। इसलिए हमारे निर्देश का तरीका अप्रभावी है। इसलिए शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। यह सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है।

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं –हमारी प्राथमिक शिक्षा अत्यधिक मुद्दों के साथ की जाती है। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों में कोई ढांचा नहीं है, बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, फर्नीचर और अध्ययन सामग्री, मूत्रालय और बिजली, और भी बहुत कुछ है। बड़ी मात्रा में ग्रेड स्कूल एकल शिक्षक स्कूल हैं और कई स्कूल शिक्षकों के बिना भी हैं। इसलिए ड्रॉप रेट अधिक है और चिंता का आधार है। हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण का मात्रात्मक विस्तार है लेकिन व्यक्तिपरक सुधार में हम अभी भी पिछड़ रहे हैं।

पुराना पाठ्यक्रम –देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। हमें शिक्षा में गुणवत्ता के साथ–साथ मात्रा भी सुनिश्चित करनी होगी। छात्र पुराने पाठ्यक्रम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भारत में बहुत सारी तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति हो रही है। और इसलिए पाठ्यक्रम स्नातक और स्नातकोत्तर हैं और आधुनिक और तकनीकी विकास के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता है।

उच्च– ड्रॉपआउट दर –शिक्षा प्रणाली में अन्य बड़ी चुनौती पब्लिक स्कूलों या सरकारी स्कूलों में उच्च ड्रॉपआउट दर है। यह सब गरीबी, शौचालयों की कमी, स्कूल की लंबी दूरी, बाल विवाह, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सांस्कृतिक कारकों जैसे कई कारकों के कारण है।

खराब शासन और जिम्मेदार शिक्षकों की कमी –हमारी शिक्षा की एक और समस्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा, इन स्कूलों में खराब प्रबंधन भी एक अन्य बड़ी समस्या है क्योंकि ये स्कूल प्रबंधन समितियां बमुश्किल कार्य कर रही हैं। साथ ही, माता–पिता अपने अधिकारों से बेखबर हैं और यह नहीं जानते कि ऐसी परिस्थितियों में किसे संबोधित किया जाए।

शिक्षकों की गुणवत्ता –प्रशिक्षित और कुशल शिक्षकों की कमी एक और समस्या है जिसका सामना हमारी शिक्षा प्रणाली करती है। कुशल शिक्षकों की कमी के अलावा, उन पर गैर–शैक्षणिक कार्यभार का भी बोझ होता है, जो शिक्षण से उनका ध्यान हटा देता है। इस प्रकार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (छप्म्।) के एक अध्ययन के अनुसार, शिक्षक केवल अपने समय का लगभग 19 प्रतिशत शिक्षण में खर्च करते हैं, जबकि उनका शेष समय ज्यादातर गैर–शिक्षण प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत होता है।

भ्रष्टाचार और धन का रिसाव –स्कूलों की उन्नति के लिए दी जाने वाली अधिकांश धनराशि भ्रष्ट मध्यस्थों द्वारा खर्च की जाती है। चूंकि ये फंड केंद्र सरकार से राज्य सरकार को स्कूलों में स्थानांतरित किए जाते हैं, इसमें कई बिचौलिये शामिल होते हैं। जिससे एक सही लाभार्थी को फंड का एक निश्चित हिस्सा ही मिल पाता है।

4 भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियां

वर्तमान अस्तित्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उन्हें इस प्रकार बताया गया हैः विषम शिक्षा प्रणाली – देश के भीतर शिक्षा प्रणाली विषम प्रकृति की है। शिक्षा प्रणाली की विषम प्रकृति का नेतृत्व करने वाले मुख्य कारक भौगोलिक स्थानों, जाति, नस्ल और व्यक्तियों की जातीय उत्पत्ति, ग्रामीण और शहरी प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों की पृष्ठभूमि में अंतर पर आधारित हैं। विभिन्न प्रकार के कॉलेज, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं जो कई कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और शिक्षा की गुणवत्ता प्रदान की जाती है। ऐसी संस्थाएँ हैं जो गुणात्मक शिक्षा का प्रावधान करती हैं और ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो शैक्षिक अनाचार में शामिल हैं।

राजनीतिक कारकों का समावेश – अधिकांश संस्थान, जब वे शिक्षा प्रदान करते हैं, प्रमुख राजनीतिक नेताओं के स्वामित्व में होते हैं। वर्तमान अस्तित्व में राजनीतिक नेता शिक्षण संस्थानों के संचालन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपने स्वयं के युवा स्टैंड स्थापित किए हैं और राजनीतिक आधार पर छात्रों के संगठन को प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों की गतिशीलता का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में, छात्रों को शिक्षा प्रबंधनीय नहीं लगती है, इसलिए वे अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विरोध भी करना शुरू कर देते हैं और कुछ मामलों में छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को भी भूल जाते हैं और राजनीति में अपना करियर बनाना शुरू कर देते हैं।

आर्थिक कठिनाइयाँ – आर्थिक कठिनाइयों को सबसे अनिवार्य परिवर्तन माना जाता है जो उच्च शिक्षा की प्रणाली ने समुदायों पर थोपा है। शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्र हैं, जो अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। बढ़ती कीमतों के कारण आर्थिक कठिनाइयों में वृद्धि हुई है, लोगों को विलासिता की वस्तुओं पर पैसा खर्च करने की आदत है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, आदि। ऐसे कई छात्र हैं जो वित्तीय समस्याओं का अनुभव करते हैं, वे अपनी शिक्षा के लिए भुगतान करने के लिए अंशकालिक नौकरियों में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें अपनी नौकरी और शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान अस्तित्व में, लगभग 75ः छात्र ऐसे हैं जो वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अंशकालिक कार्य और अध्ययन के कार्यान्वयन से उनकी आर्थिक कठिनाइयों को पर्याप्त रूप से सहायता नहीं मिल सकती है।

नैतिक मूल्यों का अभाव दृ वर्तमान विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, नवीन विधियों, आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण ने नैतिक मूल्यों को कम कर दिया है। शिक्षण संस्थानों में, कुछ मामलों में, जब शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे उन्हें फटकार सकते हैं, दूसरी ओर, छात्र शिक्षकों के साथ उचित नियम और संबंध स्थापित नहीं करते हैं, जब वे किसी भी प्रकार की फटकार का अनुभव करते हैं। . वर्तमान अस्तित्व में, हर कोई सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहेगा, पुराने छात्र शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं।

5 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव

भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुए हैं और इन्हें निम्नानुसार बताया गया है ।

एक सीखने वाले समाज की ओर – जैसा कि सीखने वाले समाज की प्रगति में होता है, प्रत्येक मानव गतिविधि को कुशल व्यक्तियों और पेशेवरों से योगदान की आवश्यकता होगी, यह उच्च शिक्षा के पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखेगा। उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों की खेती, अंतर और उन्नयन के उपायों में कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

उद्योग और शिक्षाविदों के बीच संबंध – उद्योग और शिक्षाविदों के बीच संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान अस्तित्व में, व्यक्तियों को अपने आप में कौशल और ज्ञान विकसित करना चाहिए ताकि रोजगार सुनिश्चित हो सके और कार्यों के प्रदर्शन में ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का उपयोग प्रभावी तरीके से किया जा सके। शैक्षिक संस्थानों में, कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को व्यक्तियों को विभिन्न संगठनों में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना चाहिए।

शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन– उद्योग और छात्रों की अपेक्षा है कि उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की पेशकश की जानी चाहिए। इन व्यवसायों को छात्रों के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। छात्रों के लिए पेश किए जा रहे कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यावसायिक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को विशिष्ट बनाने की आवश्यकता है

नवीन पद्धतियां – नई और आधुनिक तकनीकों के उद्भव से वर्तमान दुनिया में प्रगति होती है। यह आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण, सेवाओं की बढ़ी हुई डिलीवरी, बेहतर शिक्षा, पाठ्यक्रम और निर्देश, और सामाजिक–सांस्कृतिक उन्नति के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षा प्रणाली में नवीन पद्धतियों को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है

संसाधन जुटाना – उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए क्रियात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। ज्यादातर मामलों में, वित्त छात्रों के लिए समस्या साबित होता है, इसलिए उन्हें छात्रों की शिक्षा के लिए भुगतान करने की क्षमता के अनुसार शुल्क संरचना को विनियमित करना पड़ता है। छात्रवृत्ति की उपलब्धता ने भी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया

सूचना युग की उन्नति – दुनिया सूचना युग में प्रवेश कर रही है, संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नए, नवीन और लागत प्रभावी दृष्टिकोण का उत्पादन करेंगे। सूचना की प्रगति, व्यवसायों की तेजी से बदलती प्रकृति और आजीवन शिक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए सतत शिक्षा की आवश्यकता है

छात्र केंद्रित शिक्षा और गतिशील तरीके – उच्च शिक्षा के तरीकों को सीखने के चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, ये हैं सीखना सीखना, करना सीखना, होना सीखना और बनना सीखना। शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे छात्रों के बीच सीखने की सुविधा के लिए नवीन पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक विधियों, नए दृष्टिकोणों और रणनीतियों को अपनाएं और उनकी वृद्धि और विकास में योगदान दें।

सार्वजनिक निजी भागीदारी - Public Private Partnership पीपीपी उच्च शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता लाने के लिए मौलिक है। सरकारें उपयुक्त नीति के माध्यम से पीपीपी सुनिश्चित कर सकती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पीपीपी की दिशा में एक चरण के रूप में विश्वविद्यालयों, उद्योगों और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं छंजपवदंस त्मेमंतबी स्ंइवतंजवतपमे (एनआरएल) के बीच एक निर्धारित इंटरफेस विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। सरकार द्वारा एनआरएल को वित्त पोषण नवीनतम परिष्कृत उपकरणों की पहुंच में सहायता के लिए अनुसंधान गतिविधियों में शामिल उच्च शिक्षा के संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए

आवश्यकता आधारित नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों का प्रावधान – शैक्षिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए जो नौकरी और रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता करनी हो। एक व्यक्ति एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेता है। इसलिए, नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर आधारित हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यशालाओं और नौकरी के मेलों को व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है, जहां छात्र नौकरियों और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैंप

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग– अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा प्रणाली के विकास में प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। परिवहन और संचार के विकास में वृद्धि के साथ, एक वैश्विक गाँव अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दे रहा है और समस्याओं के संतोषजनक समाधान खोजने के लिए कार्यों को आवश्यक माना जा रहा है और उच्च शिक्षा उनमें से एक है ८

एक नई दृष्टि की ओर – देश के भीतर शिक्षा प्रणाली का विस्तार इसके संवर्धन, वृद्धि और विकास में काफी हद तक योगदान देगा। समाज शारीरिक, भावनात्मक, गतिशील, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यपरक और आध्यात्मिक क्षमताओं से प्रभावित होता है, इसलिए शिक्षा आधुनिक और नवीन दृष्टिकोणों, रणनीतियों और विधियों के विकास में योगदान देगी जो उन्नति की ओर ले जाएगी।

क्रॉस कल्चर प्रोग्राम – भारत में, विभिन्न संस्कृतियाँ, जातियाँ, धर्म, नस्लें, नस्लें, कलाएँ, क्षेत्र आदि हैं। शिक्षा लोगों को एक–दूसरे की संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और समझने में सक्षम बनाएगी, जिससे वे एकता में रह सकेंगे और एक–दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अन्य संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों

की जानकारी प्राप्त करने से लोग एक टीम के रूप में सहयोग करने और एक दूसरे के साथ काम करने में सक्षम होंगे

गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना – शैक्षणिक गतिविधियों के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए, विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा कॉलेजों में तीन साल में एक बार अकादमिक और प्रशासनिक ऑडिट करना महत्वपूर्ण है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को पहचान कर उत्पादक तरीके से लागू किया जाना चाहि, जिससे शिक्षा की प्रणाली में प्रगति हो।

व्यक्तित्व – शिक्षा प्रणाली के भीतर, पाठ्येतर गतिविधियों को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति सीखने में रुचि लें और इसे आनंदपूर्वक सीखे । विभिन्न प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियों में खेल, शारीरिक गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प शामिल होंगे। इन गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी उनकी मानसिकता को उत्तेजित करती है और उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है।

उच्च शिक्षा का निजीकरण - किसी भी राष्ट्र में शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता है जो व्यक्तियों और समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास की ओर ले जाती है। व्यक्तियों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों और प्रक्रियाओं को तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि भारत में शिक्षित लोगों की दर कम है, और देश के विकास के लिए इसे बढ़ाना होगा।

गुणवत्ता का विकास – शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का विकास शिक्षाविदों, पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक रणनीतियों, शिक्षण–शिक्षण विधियों, शैक्षणिक कार्यक्रमों, अनुसंधान और छात्रवृत्ति, कर्मचारियों, छात्रों, भवन, सुविधाओं, उपकरण, प्रौद्योगिकी, सेवाओं के विकास से संबंधित है। समुदाय और शैक्षणिक वातावरण के लिए ज्ञान का आदान–प्रदान, शिक्षकों और छात्रों की गतिशीलता, इंटरएक्टिव नेटवर्किंग और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं गुणवत्ता विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं।

विश्व स्तर की शिक्षा – ऐसे कई भारतीय छात्र हैं जो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विदेशी विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों को पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी उच्च शिक्षा की अनुमति देते हैं। इसी तरह, भारतीय विश्वविद्यालय भी विदेशी छात्रों के लिए शिक्षा का प्रावधान करते हैं। इसलिए, शिक्षण संस्थानों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को अपनाना महत्वपूर्ण है।

व्यक्तित्व विकास – शिक्षा की प्रणाली को व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास को उचित तरीके से सक्षम बनाना चाहिए। इसे न केवल अकादमिक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए बल्कि व्यक्तियों को अधिक रचनात्मक, आविष्कारशील, साधन संपन्न और सरल बनाने में भी मदद करनी चाहिए। एक सुशिक्षित व्यक्ति इस बात से अवगत होता है कि घर, कार्यस्थल और समुदाय के भीतर अन्य लोगों के साथ कैसे संवाद और व्यवहार करना है।

अकादमिक अनुसंधान अध्ययन की स्थिति – उच्च शिक्षा में, अनुसंधान को एक अनिवार्य क्षेत्र माना जाता है जिसे प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टरेट कार्यक्रमों में, छात्रों को डेटा और अन्य जानकारी के संग्रह में व्यापक पैमाने पर अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान दो प्रकार के होते हैं, एक क्षेत्र अनुसंधान है, जिसे क्षेत्र में लागू किया जाता है और इसमें संगठनों, संस्थानों या अन्य क्षेत्रों के भीतर अन्य लोगों के साथ शोधकर्ता का संचार शामिल होता है और दूसरे प्रकार का शोध पुस्तकों, दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी के संग्रह में किया जाता है। , लेख, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और इंटरनेट इसलिए, उन उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है जो अकादमिक शोध अध्ययनों में सुधार लाएंगे।

छात्रवृत्ति की उपलब्धता – भारत में, व्यक्तियों ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है, यहां तक कि जो वंचित, हाशिए पर और समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं, वे भी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ज्यादातर मामलों में, वित्त उन व्यक्तियों के लिए प्रमुख समस्याएँ हैं जो अध्ययन करने के इच्छुक हैं, ये समस्याएँ उनके शिक्षा के अधिग्रहण के दौरान बाधाएँ हैं, इसलिए, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की उपलब्धता काफी हद तक प्राप्ति में योगदान करेगी शिक्षा।

उचित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली – कॉलेजों और निजी संस्थानों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली स्थापित करने और डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानक अपनाने की आवश्यकता होती है। गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को राजनीतिक और संस्थागत बातचीत से स्वायत्त होना चाहिए और कानून में इसका आधार होना चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ क्रियाशील, आर्थिक और शैक्षिक स्वशासन होना चाहिए। सरकार, उद्योग, शिक्षा, समाज आदि के एक निगम के साथ एक स्वतंत्र प्राधिकरण एजेंसी की आवश्यकता है, इसका मतलब शिक्षा के सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना है छात्रों को ध्यान में रखते हुए ।

विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि – विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि से नवीन प्रक्रियाओं और विधियों का निर्माण होगा जो शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक हैं। भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य होना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में प्रगति के लिए बड़े पैमाने पर योगदान देना चाहिए।

परीक्षा और मूल्यांकन तकनीक – मूल्यांकन तकनीक को अनिवार्य माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमताओं का आकलन करना है और वे कितना समझ चुके हैं। परीक्षाओं को सबसे महत्वपूर्ण

तकनीकों में से एक माना जाता है जो छात्रों की स्थिति और प्रदर्शन का आकलन करती है। परीक्षाओं के संचालन को नियमित और सुसंगत तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर क्षेत्र में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, उनकी कमजोरियों की पर्याप्त रूप से पहचान की जाती है और फिर उन्हें सुधारने के लिए उचित उपायों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

हाई–टेक पुस्तकालय – देश के कुछ हिस्सों में, शैक्षणिक संस्थानों में, पुस्तकालय अविकसित अवस्था में हैं। पुस्तकालयों को उन क्षेत्रों के रूप में संदर्भित किया जाता है, जहाँ पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों और अन्य दस्तावेजों का संग्रह होता है। उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में कंप्यूटर और इंटरनेट की भी उपलब्धता है जहाँ छात्र उनका उपयोग करने में सक्षम हैं। गंभीर अध्ययन के लिए एक पुस्तकालय ऑनलाइन और अनुकूल होना चाहिए । यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पुस्तकालय चाहे नर्सरी स्कूलों, अन्य स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में हों, उन्हें अच्छी तरह से विकसित किया जाना चाहिए, उचित तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और सभी विषयों से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए जो व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान अस्तित्व में, ज्यादातर मामलों में, छात्र इंटरनेट के अलावा पुस्तकालयों पर निर्भर हैं।

6 निष्कर्ष

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वह अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी हासिल करने, व्यक्तियों को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने, नैतिकता, नैतिकता, शालीनता और शालीनता के गुणों को स्वयं में विकसित करने और उनके व्यक्तित्व के विकास में प्रभावी योगदान देने में योगदान मिलेगा। वर्तमान अस्तित्व में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में समस्याएँ रही हैंय मुद्दे हैं, शिक्षण विशेषता निम्न स्थिति में है, वित्तीय बाधाएँ, पारंपरिक शिक्षण विधियाँ, निजीकरण, अपर्याप्त सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा और इनाम रचनात्मकता, मूल सोच, अनुसंधान और नवाचार। चुनौतियाँ हैं, विषम शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक कारकों की भागीदारी, आर्थिक कठिनाइयाँ और नैतिक मूल्यों की कमी। देश में शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैंय एक सीखने वाले समाज की ओर, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच संबंध, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन, नवीन प्रथाओं, संसाधनों का जुटाव, सूचना युग की उन्नति, छात्र केंद्रित शिक्षा और गतिशील तरीके, सार्वजनिक निजी भागीदारी, आवश्यकता आधारित नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एक नई दृष्टि की ओर, क्रॉस कल्चर प्रोग्राम, गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना, व्यक्तित्व, उच्च शिक्षा का निजीकरण, गुणवत्ता विकास, विश्व स्तरीय शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, अकादमिक शोध अध्ययन की स्थिति, छात्रवृत्ति की उपलब्धता, उचित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली , विश्वविद्यालयों, परीक्षाओं और मूल्यांकन तकनीकों, और हाई–टेक पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि करना। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विकास हो रहा है। सभी क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के व्यक्ति शिक्षा के महत्व को महसूस कर रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है और सीखने–सिखाने के तरीकों में प्रगति हुई है। दूसरी ओर, समस्याओं का होना बाधाएँ सिद्ध होती हैं, जिन्हें दूर करने या संशोधित करने की आवश्यकता होती है। उपयुक्त उपायों और नीतियों का निर्माण होना चाहिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन से भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास होगा।

References:

- Chahal, M. (2015). Higher Education in India: Emerging Issues, Challenges and Suggestions. *International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research,1(11),* 67-74. Retrieved September 19, 2017 from http://ijbemr.com/wpcontent/uploads/2015/05/Higher_Education_in_India_Emerging_Issues_Challenges_and_Suggestions.pdf
- Chakrabarty, K.C. (2011). Indian education system – Issues and Challenges. Retrieved September 19, 2017 from http://www.bis.org/review/r110809b.pdf
- Challenges in Indian Higher Education – Indian Context. (n.d.). Retrieved September 19, 2017from
- Lall, M. (2005). The Challenges for India's Education System. Retrieved September 19, 2017 from http://marielall.com/wp/wp-content/uploads/Chatham-house-indiaeducation.pdf
- Singh, J.D. (n.d.). Higher Education in India – Issues, Challenges and Suggestions. Retrieved September 19, 2017 from http://www.gvctesangaria.org/websiteimg/publications/jdarticle.pdf
- Thanky, P. (2013). Education System in Present Scenario: Problems & Remedies. *Indian Journal of Applied Research, 3(7),* 166-167. Retrieved September 19, 2017 from https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-researc (IJAR)/file.php?val=July_2013_1372686339_45dd6_49.pdf
- Varghese, N.V., & J.B.G. Tilak. (1991). The financing of education in India. International Institute for Educational Planning. Retrieved September 19, 2017 from

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000902/090282eo.pdf

- Chandrupatla, T. R. (2009). Quality and Reliability in Engineering. Cambridge University Press, 978-0-521-51522-1.
- Juran, J.M., Gryna, F.M., Jr. and Bingham, R.S. (1988), Quality Control Handbook, 4th edition.New York: Mc Graw Hill.
- Ministry of Human resource Development, Department of Higher Education. (2017). All India Survey on Higher Education (2016-17), Government of India, New Delhi.. Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education. (2013). All India
- Survey on Higher Education (2010-11), Government of India. New Delhi. Ministry of Human Resource Development. (2015). Analysis of Budgeted Expenditure on Education 2012-13 to 2014-15, Government of India, New Delhi.
- Pandya, P.J. (2016). Improving Quality of Higher Education in India. An Inter Disciplinary National Peer & Double Reviewed e-Journal of Languages, Social Sciences and Commerce ISSN No: 2455-734X.
- Pujar, U. (2014). Trends in Growth of Higher Education in India. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF, Volume 2, (Issue 6).
- Rao, I. (2016). Sustainable Development of Higher Education Problems and Suggestions. Sai Om Journal of Commerce & Management, Volume 3, (Issue 9).
- Shaguri O. R. (2013). Higher Education in India- Access, Equity, Quality. Ean World Congress Scholar 2013.
- Singh, J. D. (2011). Higher Education in India– Issues, Challenges and Suggestions, (Ed), 'Higher Education', LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2011, Pp.93- 103. ISBN: 978-3-8465-1753-6.
- University Grants Commission. (2017). Annual Report 2016-17, New Delhi. Retrieved from http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ABE2012-15_0.pdf
- University Grants Commission. (2018). Consolidated list of All Universities. Retrieved from https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20Universities.pdf
- Zaki, S. and Zaki, R. M.(2013). Parameters of Quality in Higher Education: A Theoretical Framework. International Journal of Social Science & Education, Volume.3 (Issue 4)